B.A Part 2
Paper IV+V

राज्य सरकारों के बजटों का वर्गीकरण :-
(Classification of State budget)

भारत सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुरूप राज्य में भी बजटों के वर्गीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। प्रारंभ में राज्य सरकारों के बजटीय आर्थिक वर्गीकरण में तीन विवरण थे, अर्थात् –

विवरण संख्या 1: प्रशासनिक विभागों का आय और परिव्यय खाता।
विवरण संख्या 2: विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का उत्पादन खाता।
विवरण संख्या 3: सामान्य सरकार का वित्त-पोषण खाता।

इस प्रकार विदित होता है कि प्रारंभ से ही राज्यों द्वारा अपनाया गया आर्थिक वर्गीकरण केन्द्रीय सरकार के वर्गीकरण की तुलना में बहुत संकीर्ण था। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, तथा मिलान के विवरण नहीं थे, तथा इनमें दर्शाई गई मदों में भी सुधार की अधिक गुंजाइश थी।

इसके अतिरिक्त राज्यों के आर्थिक - कार्यात्मक वर्गीकरण की रूपरेखा भी केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाए गए ढाँचे के अनुरूप नहीं थी। आर्थिक वर्गीकरण के दो भाग थे, अर्थात्

(क) पूँजी व्यय; और
(ख) राजस्व व्यय।

इन दोनों भागों में अपने-अपने मद-वर्ग और अवर्गी थे। इसी प्रकार कार्यात्मक वर्गीकरण के भाग में 9 मुख्य मद-समूह थे, अर्थात्

1) सामान्य सेवाएँ;
2) रक्षा (इस भाग में कोई राशि नहीं होती);
3) शिक्षा;
4) स्वास्थ्य;

Scanned by CamScanner

(5) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की स्कीमें ;
(6) आवास तथा सामूहिक सेवाएँ ;
(7) सांस्कृतिक, मनोरंजन तथा धार्मिक सेवाएँ ;
(8) आर्थिक सेवाएँ ;
(9) अन्य सेवाएँ ; तथा
(10) कुल जोड़ ।

विदित है कि राज्यों के बजटों का कार्यात्मक वर्गीकरण केन्द्र के कार्यात्मक की तुलना में अधिक विस्तृत था । इसमें कोई 'अवर्गीकृत व्यय मद नहीं थी, जो स्वयं में एक श्रेयस्कर उपलब्धि थी।

निष्कर्ष – स्पष्ट है कि सरकार के सभी स्तरों (केन्द्रीय, राज्यीय और स्थानीय) के बजटों के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरणों की उपयोगिता में बढ़ोतरी करना आवश्यक भी है और संभव भी । इस उद्देश्य हेतु निम्नलिखित सुझावों को अपनाने की सिफारिश की जा सकती है –

- पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण का एक ऐसा नया, उपयोगी और संरचनात्मक स्वरूप तैयार किया जाए जिसे सरकार के सभी ~~सत्रों~~ स्तरों पर अपनाया जा सके ;
- सरकार के सभी स्तरों पर इस नए वर्गीकरण को अपनाया जाए ;
- सरकार की सभी स्तरों के बजटों के वर्गीकरणों को विधिवत और बिना देरी के तैयार और प्रकाशित करें ;
- सरकार के सभी स्तरों के बजटों का एकीकृत वर्गीकरण विधिवत और बिना देरी के तैयार और प्रकाशित किया जाए ;
- इस एकीकृत वर्गीकरण के अनुरूप पूरी अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों को भी वर्गीकृत किया जाए ।

Scanned by CamScanner

परंतु, उपरोक्त सुझावों में से किसी को भी न अपनाए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार और राज्यों के बजटीय वर्गीकरणों से प्राप्य जानकारी और नीति-सहायता का लाभ नहीं उठाया जा सका। उलटे कालान्तर में केन्द्रीय बजट के वर्गीकरण भी कम हो गई है। इसका एक कारण यह भी है कि कालान्तर में राज्यों की अपने बजटों के वर्गीकरण के बारे में उदासीनता बढ़ती गई है। वर्तमान स्थिति यह है कि अधिकतर मामलों में

- राज्यों इस वर्गीकरण के अस्तित्व और आवश्यकता को लगभग भूल चुके हैं; अथवा
- उन्होंने इसमें अपनी इच्छानुसार संशोधन कर लिए हैं; अथवा
- इस वर्गीकरण के औचित्य को स्वीकारते हुए भी इसके विवरण और आंकड़े उपलब्ध नहीं कराते; अथवा
- केवल राज्य की 'आर्थिक समीक्षा' में इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दी जाती है; अथवा
- प्रकाशित जानकारी वर्षों पुरानी होने के कारण बेकार होती है।

परंतु इन सब त्रुटियों का यह अर्थ नहीं बनता कि बजटों का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण बेकार है। इसके विपरीत परिणाम यह निकलता है कि इसमें यथोचित सुधार द्वारा तथा व्यापक रूप से अपनाते हुए विश्लेषणात्मक और नीति उपयोगी बढ़ानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यानयोग्य है कि कार्यात्मक वर्गीकरण 'कार्यक्रम एवं निष्पादन बजटिंग' (programming and performance budgeting) जैसे अर्थपूर्ण और उपयोगी बजटीय विधियों की संरचना में भी सहायक सिद्ध होती है।

Scanned by CamScanner